LOK SABHA

Thursday, April 1, 1965/Chaitra 11, 1887 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Speaker: I feel a little ashamed when I have to enter the House after it is Eleven O' Clock.

An hon. Member: You came in time, Sir.

Mr. Speaker: No. The Bell had to be rung. The quorum was not there, and I have come after the Bell was rung. Therefore, I may request hon. Members that they should be present.

Shri Yashpal Singh: It is the responsibility of the ruling party.

Mr. Speaker: Every hon. Member should realise it.

Shri Kapur Singh: When hon. Members see Shri Yashpal Singh's name on every question, they keep themselves away.

Shri A. S. Saigal: The responsibility is that of all parties and not only the ruling party.

Mr. Speaker: Order, order. Let us proceed now.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Scarcity of Houses in Delhi

\+

*681. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Buta Singh:
Shri Yudhvir Singh:

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the scarcity of houses for Government employees in Delhi;

(b) if so, the number of houses to be constructed by Government by the end of the Third Plan period;

(c) the tentative programme prepared by Government to remove the acute shortage of houses in the Capital; and

(d) the estimated amount to be spent thereon?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes, Sir.

(b) About 10,400 of which 6,000 have been completed and 4,400 are under construction. There is sanction for another 4,000 approximately.

(c) and (d). For construction of houses to meet the present entire demand of Central Government employees in the general pool in Delhi, about Rs. 63 crores will be needed. The programme of construction will be spread over several years in accordance with the funds that may be made available.

श्री यशपाल सिंह : इस हाउस में दो साल से यह आवाज उठ रही है कि संसद सदस्यों के मकानों के किराए बढ़ाए जायें । इनके मकानों के किराए चाहे चौगुने कर दिए जायें, लेकिन इन्हें

ऐसे मकान दिये जायें जैसे जन प्रतिनिधियों को दिए जाने चाहिये, जिनका ताल्लुक लाखों आदमियों से है। अभी उन को छोटे छोट कमरों में बन्द कर रखा है। जब कोई मेहमान आता है तो यह अवस्था हो जाती है कि वहीं सिगरेट पीने वाला बैठता है, और वहीं वेद भगवान का पाठ करने वाला बैठता है जिससे अनैतिकता फैल रही है। इस मामले में सरकार क्या कर रही है। संसद् सदस्यों के मकानों के किराए चाहे बढ़ा दिये जायें लेकिन उन को सूटेबिल एकोमोडेशन दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : सवाल तो गवर्नमेंट एम्प्लाईज का है।

श्री यशपाल सिंह : हम भी तो गवर्नमेंट सरवेंट हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक मेम्बर पार्लियामेंट साहिबान का ताल्लुक है, जिनको जगह चाहिए उन तमाम के तमाम को जगह मिल चुकी है। अभी हम ने वल्लभ भाई पटेल हाउस बनवाया है। उस के किराए का फसला हो चुका है, आज या कल में मैं स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखने वाला हूं ....

अध्यक्ष महोदय : आप अभी हाउस को बतला दें तो अच्छा हो क्योंकि किराए का फैसला तो हो ही चुका है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप मुझे इजाजत दें तो कल मैं स्टेटमेंट रख दूंगा। इस वक्त एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं हैं।

श्री यशपाल सिंह : वह तो होस्टल है।

जो मकानात छोटे कर्मचारियों के लिए दो साल से बने पड़े हैं, उनको अभी तक इसलिए एलाट नहीं किया जा सका है कि बिजली पानी का इन्तिजाम नहीं हुआ। यह इन्तिजाम कब तक हो जाएगा।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बात दुरुस्त नहीं है। जो मकान हम ने बनाए हैं वे सब के सब एलाट हो चुके हैं। सिर्फ राम कृष्ण पुरम में थोड़े दिनों से पानी की किल्लत है। इस वक्त जो आठ सौ या नौ सौ मकान तैयार हो रहे हैं दो महीने के अन्दर उन को पानी मिल जाएगा और हम वह भी एलाट कर देंगे। मुझे खुद भी तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि मकान बन गए हैं और उन को पानी नहीं मिला।

Shri S. M. Banerjee: I went to know whether it is a fact that still, as on today, nearly 62,800 government employees are waiting to get some accommodation in Delhi; if so, may I know whether there is any scheme to provide two-roomed tenements at least to those employees during the Fourth Plan and how many quarters are likely to be built in the Fourth Plan?

Shri Mehr Chand Khanna: It is a fact that the total demand in Delhi is about a lakh or a little over a lakh, and I have only about 35,000 houses in the pool. Thereby, there is a deficit of about 65,000 houses in Delhi alone. We are doing our best to bridge the gap. Two things we have done in the meanwhile. One is, in future we are going to undertake construction only for government servants who are in the lower category. According to the revised classification the categories are from 1 to 8. We propose to build houses for government servants who are in the category of 1 to 4 because there the gap is the biggest. Secondly, a decision has been taken that as for the government servants who are in category 1—that is, class IV employees—we will provide them with two-roomed houses in future.

Shri Indrajit Gupta: Shri Banerjee's question was how many quarters are going to be built in the Fourth Plan?

Shri Mehr Chand Khanna: As regards the Fourth Plan, as against a total allocation of Rs. 25 crores which the Finance Minister was kind enough to increase to Rs. 35 crores, I am getting an allocation of Rs. 80 crores—that is, more than double.

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए लोन देने को जो रुपया रखा गया था वह सारा दे दिया गया है या उस में से कुछ बाकी है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक गवर्नमेंट सरवेंट्स को मकान के लिये कर्ज का ताल्लुक है वह सोशल हाउसिंग स्कीम में मिलता है । वह तो राज्य सरकारों के मारफत लोन दिया जाता है मकान बनाने के लिए । यह वह चीज है जो हम खुद बनाते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : भिन्न भिन्न राज्यों से जब सरकारी कर्मचारी दिल्ली में आते हैं तो उन्हें मकान की काफी दिक्कत होती है । क्या सरकार इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए छः छः, सात सात, आठ आठ मंजिल के मकान बनाने का विचार कर रही है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पहली बात का जवाब तो हां में है । बाहर से जो लोग आते हैं उनको मकान के लिए बहुत सालों तक इन्तिजार करना पड़ता है । उसकी वजह यह है कि हम ने काफी मकान पीछे नहीं बनाए । गवर्नमेंट बढ़ती गई लेकिन उस के मुकाबले में मकान नहीं बनाए गए । अब हम यही चीज करना चाहते हैं । अब हम यह विचार कर रहे हैं और मैं ने आगे हाउस में भी यह बतलाया है, कि हम मल्टी स्टोरीड कांस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेजीडेंशियल भी और आफिसेज के लिए भी ।

श्री युद्धवीर सिंह : दिल्ली के अन्दर सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की कमी को देखते हुए क्या कोई ऐसी योजना चालू करने का सरकार विचार कर रही है कि उनको मकान बनाने के लिए कर्जा दिया जाए, जमीन दी जाए और मकान बनाने के सामान की सुविधा दी जाए । अगर अभी ऐसी योजना नहीं है तो क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना चालू करने का विचार सरकार का है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमारे पास स्कीमें हैं, लो इनकम ग्रुप वालों के लिए मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए और सेन्ट्रल गवर्नमेंट सरवेंट्स के लिए भी स्कीमें हैं, जिन के लिए उन को लोन दिया जाता है । लेकिन यह दिल्ली सरकार के मारफत दिया जाता है और मुझे इस में कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती ।

श्री रा० स० तिवारी : दिल्ली में केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही मकानों की कमी नहीं है, दीगर लोगों के लिए भी मकानों की कमी है । क्या जो कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस को इस वक्त कर्मचारियों तक ही रहने दीजिए ।

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether sub-letting of houses by government servants to other government servants is prohibited and whether the rent given to them is very very low?

Mr. Speaker: Why should we go into sub-letting at this moment?

Increase in Bank Rate

+

*682. { **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri D. N. Tiwary:** **Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 205 on the 26th November, 1964 and state:

(a) the reaction of the investors to the increase in the bank rate by the scheduled banks; and

(b) whether the increase in the bank rate has had any adverse effects on the borrowers?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) The bank rate and other rates of interest generally have been increased, for reasons which have already been explained in great